भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2417
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2417. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्य में खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश में मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी ढांचे के कारण रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

(ख): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है । पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई निधियों में केंद्र के हिस्से का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग) एवं (घ): मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये योजनाएं क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अब तक उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई की समरूपी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 27 एकीकृत शीत श्रृंखला, 37 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 5 बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 4 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 45108 रोजगार के अवसरों के सृजन का अनुमान है। बहराइच जिले में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 15,586 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है , जिससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 46758 रोजगार के अवसरों के सृजन का अनुमान है , इसमें से बहराइच जिले में 166 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 30738 रोजगार अवसरों के सृजन का अनुमान है । बहराइच जिले में पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तर देने हेतु "उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2417 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी धनराशि

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उत्तर प्रदेश	24.08 करोड़	21.06 करोड़	79.55 करोड़	150 करोड़

*****